सच्ची मुच्ची

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की पत्रिका

जनवरी 2012

– लोक राजनीति मंच एक वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसका इस देश में संविधान में पूरा भरोसा हो तथा जो भ्रष्ट–आपराधिक गठजोड़ का मुकाबला भी करने को तैयार हो –

2012 उ.प्र. विधान सभा चुनाव में लोक राजनीति मंच के उम्मीदवार

- **पिपराइच, गोरखपुर, सत्येन्द्र यादव,** समाजवादी जन परिषद, 9795750713
- **बेल्थरा रोड, बलियाः जितेन्द्र त्यागी,** समाजवादी जन परिषद, 9792509921
- **वाराणसी कैण्टः अफलातून देसाई,** समाजवादी जन परिषद, 0542 2575063
- **वाराणसी उत्तरीः अनीता श्रीवास्तव**,9452561486
- **सफीपुर (सुरक्षित), उन्नावः सुषमा,** 9919577819
- **सण्डीला, हरदोईः रमदई,** 7607507289
- **मुहोली,सीतापुरः देवेश पटेल**,9455037799

उ.प्र. सम्पर्कः नंदलाल, वाराणसी, 9415300520, जे.पी. सिंह, बलिया, 9839333205, अनिल मिश्र, उन्नाव, 9956501581, भगवानदीन, हरदोई, 9919823845, राम सेवक, सीतापुर, 9005676411, प्रेम कुमार, मुरादाबाद, 9412839020, राजेश मौर्य, बाराबंकी, 9807289239, लखनऊः देवेश पटेल, 9455037799, 9235977799, चुन्नीलाल, 9839422521, मुन्नालाल, 9452755765, एस.आर. दारापुरी, 9415164845, संदीप पाण्डेय, 0522 2347365, अजीत झा, दिल्ली, 09868920697

विषय सूची

1. भ्रष्टाचार और राजनीतिक बदलाव................ 3
2. निर्णय खुली बैठक में लूँगीः रमदई............... 6
3. लोकतंत्र और राजनीति पर नियंत्रण..............8
4. जन–विरोधी 'कारपोरेट' राजनीति.................10
5. किसान खत्म किया जा रहा है.......................12
6. महिला असमानता और भ्रष्टाचार...................15
7. कैफी आज़मी की याद में................................17
8. सरकारी कर्मचारी क्यों घूस माँगते हैं?.........19
9. पैगाम–ए–अमन कारवाँ..................................20
10. आगामी कार्यक्रम..22
11. लोक राजनीति मंच की आचार संहिता......23
12.लोक राजनीति मंच की वैकल्पिक राजनीति..24

सच्ची मुच्ची

वर्ष 11: अंक 1 जनवरी 2012

सम्पादक मण्डल
एस.आर.दारापुरी 9415164845
नागेश त्रिपाठी 9452112004
अरविन्द मूर्ति 9839835032
रोमा 9415233583
राजीव यादव 9452800752
शाहनवाज़ आलम 9415254919
ईमेलः ashaashram@yahoo.com
फैक्सः 0522–2358230

सलाहकार मण्डल
मेधा पाटकर, अरूणा राय, कविता श्रीवास्तव, योगेन्द्र यादव, अजीत झा, रवि किरण जैन, नीलाभ मिश्र, अजीत साही, जे.पी. सिंह, डॉ. सुनीलम्

व्यवस्थापकीय सम्पर्कः
डॉ. संदीप पाण्डेय
ए–893, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016.उ0प्र0
फोनः 0522–2347365, 9839073355
ईमेलः ashaashram@yahoo.com

विज्ञापन: देवेश पटेल 9919841007
वितरण: वल्लभाचार्य, प्रदीप सिंह
'लेआउट, डिज़ाइन, प्रकाशन':
सी.एन.एस. www.citizen-news.org

सहयोग राशिः रूपये 10 मात्र
वार्षिक सहयोग राशिः रूपये 100 मात्र
वार्षिक सहयोग राशि मनीआर्डर द्वारा व्यवस्थापकीय पते पर भेजें।

भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी

अण्णा हजारे के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन से लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गईं हैं। इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिलने के पीछे एक बड़ा कारण रहा लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश। सामान्य लोग भ्रष्टाचार से इतने पीड़ित हैं कि जैसे ही उन्हें अण्णा के आंदोलन में इसका समाधान दिखाई पड़ा उन्होंने इस आंदोलन को हाथों हाथ ले लिया।

किन्तु क्या वाकई एक लोकपाल कानून बन जाने भर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? इस देश में किस कानून का कड़ाई से पालन हो पाता है? क्या कानून से बचने का कोई न कोई रास्ता निहित स्वार्थ वाले खोज नहीं लेते? क्या इसकी सम्भावना नहीं है कि न्यायपालिका की तरह लोकपाल भी भ्रष्ट हो जाए?

फिलहाल तो एक मजबूत लोकपाल कानून बन जाएगा इसकी सम्भावना भी नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि वामपंथी दलों को छोड़ शायद कोई दल

यह नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ा कानून बने। उनके संसद में लोकपाल विधेयक पर रुख से यह बात साफ है। आखिर जो लोग भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव जीत कर आए हैं वे कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे? वर्तमान राजनीतिक तंत्र का वित्तीय पोषण भ्रष्टाचार के पैसे से होता है यह अब कोई छिपी बात नहीं है। यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो आज की तारीख में जो सांसद चुने गए हैं उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। उनमें से ज्यादातर लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आखिर तीन सौ से ऊपर करोड़पति और डेढ़ सौ से ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद इस देश के सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व तो करते नहीं? ये सामान्य तरीके से या सहज रूप से चुनाव जीत कर आए हुए लोग नहीं हैं। इन्होंने पैसे के बल पर या कोई न कोई गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर अपने मत प्राप्त किए हैं। यही राजनीतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण है।

वर्तमान राजनीतिक तंत्र का वित्तीय पोषण भ्रष्टाचार के पैसे से होता है यह अब कोई छिपी बात नहीं है। यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो आज की तारीख में जो सांसद चुने गए हैं उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। **उनमें से ज्यादातर लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे।**

इस भ्रष्ट राजनीति जिसपर अब आपराधिक किस्म के लोगों का कब्जा है के विकल्प को खड़ा किए बगैर भ्रस्टाचार खत्म कर पाना असम्भव है। वैकल्पिक राजनीति का स्वरूप क्या होगा?

सबसे पहले तो राजनीति में ऐसे लोगों को आना होगा जिनकी जीवन शैली दिखावे से दूर हो। जो कम पैसे में चुनाव लड़ सकें। **चुनाव आयोग द्वारा तय की गई खर्च की सीमा भी काफी अधिक है। उदाहरण के लिए विधान सभा चुनाव में खर्च की सीमा रु. 16 लाख है।** कौन सामान्य व्यक्ति इतना पैसा खर्च कर सकता है? चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार की जीवन शैली में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि उसका जीवन खर्चीला हो जाता है तो यह तय है कि वह जन प्रतिनिधि भ्रष्टाचार से ही अपनी जरूरत पूरी करेगा। सुरक्षा के लिए उसे हथियार रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। असली जन प्रतिनिधि तो वह है जिसे उस जनता के बीच जाकर तो और सुरक्षित महसूस करना चाहिए जिसने उसे चुना है। वैसे भी कई बड़े राजनेताओं की हत्या ने यह दिखा दिया है कि हथियारों से मनुष्य की सुरक्षा नहीं होती।

राजनीति करने वाला व्यक्ति जमीनी कार्यकर्ता भी होना चाहिए, तभी वह जनता का दुख–दर्द भली भांति समझ पाएगा। जनता की उस तक सीधी पहुंच होनी चाहिए। जनता को ऐसा

लगना चाहिए कि उसका जन प्रतिनिधि उसी के बीच का व्यक्ति है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, खासकर देश के लिए नीतियां बनाने वक्त उसे जनता से सलाह मशविरा करना चाहिए। अपने दल या दल के नेता की बात मानने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। उसके जीवन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।

अण्णा हजारे का आंदोलन यह तो कह रहा है कि कांग्रेस को मत न दो किन्तु यह नहीं बता रहा कि किसे मत दो। फिर कांग्रेस के विकल्प में जो जीत कर आएगा, वह तो अन्य किसी मुख्य धारा के दल का ही सदस्य होगा। जब सारे दल भ्रष्टाचार के पैसों पर राजनीति करते हैं तो कोई और भ्रष्ट कांग्रेस से बेहतर कैसे हो सकता है? असल में हमें कांग्रेस का विकल्प नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का विकल्प चाहिए।

यहीं अण्णा हजारे का आंदोलन गल्ती कर रहा है। जब आप भ्रष्टाचार का विकल्प खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो किरण बेदी उसका हिस्सा नहीं हो सकतीं। किरण बेदी के जो कारनामे सामने आए हैं उन्हें कैसे जायज ठहराया जा सकता है? करना कुछ अलग और कागज पर कुछ और दिखना, इसे ही तो भ्रष्टाचार कहते हैं। यदि स्वामी अग्निवेश की एक गल्ती पर उन्हें आंदोलन से अलग किया जा सकता था तो किरण बेदी को क्यों नहीं किया गया? क्या यह माना जाए कि अण्णा हजारे का आंदोलन भी कुछ हद तक भ्रष्टाचार बरदास्त कर सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अब यह हमारे खून में बस गया है। यानी आप कुछ भी कर लें यह खत्म नहीं हो सकता।

लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि यह आंदोलन ही क्यों चलाया जा रहा है? यदि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यह कहना कि किरण बेदी ने प्राप्त अतिरिक्त धन सामाजिक कामों में लगाया भी कोई मजबूत दलील नहीं है। हरेक भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कुछ कम कुछ ज्यादा हद तक उसे जायज ठहराने वाला तर्क ढूंढ ही लेगा।

पूरी संस्कृति ही बदलनी पड़ेगी। यदि खून में भ्रष्टाचार समा गया है तो उसे कैंसर मान कर पूरा खून ही बदलना पड़ेगा। यह परिवर्तन राजनीतिक ही होना पड़ेगा क्योंकि वहीं इसकी जड़ है। यदि राजनेता चाह लेंगे तो नौकरशाही का भ्रष्टाचार भी रोका जा सकता है हलांकि कुछ लोगों का मानना है कि नौकरशाही ज्यादा भ्रष्ट है क्योंही उसे ही भ्रष्टाचार के तरीके मालूम है। खैर माहौल बदलेगा तो लोग भी बदलेंगे ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।

– डॉ. संदीप पाण्डेय

निर्णय खुली बैठक में लूँगी:
रमदई, सण्डीला, हरदोई से प्रत्याशी

रमदई, एक दलित महिला हैं जो लोक राजनीति मंच की ओर से संडीला, हरदोई से 2012 विधान सभा प्रत्याशी हैं।

रमदई ने बताया कि सरकार के खाद्यन्न कार्यक्रमों – सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यांह भोजन व आंगनवाड़ी – को देखें तो काफी कोशिशों के बावजूद इनकी गुणवत्ता एक हद से ज्यादा सुधार पाना मुश्किल होता है। ये सरकार के अन्य कार्यक्रमों की तरह बुरी तरह भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं और इनके लिए कोई गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये मान लिया गया है कि सरकार का पैसा है तो दुरुपयोग तो होना ही है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली–भरावन क्षेत्र के लालपुर गांव में स्थित आशा आश्रम पर इसीलिए एक लंगर आरंभ हुआ जिसका समन्वयन रमदई करती हैं। प्रतिदिन लगभग ८०–८५ लोग इस लंगर में भोजन करते हैं।

रमदई के तीन छोटे–छोटे बच्चे हैं, पति वर्षों पहले जीवित नहीं रहे, और कोई आर्थिक जमा–पूँजी भी नहीं है. तब से रमदई मजदूरी आदि कर के किसी तरह

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली–भरावन क्षेत्र के लालपुर गांव में स्थित आशा आश्रम पर इसीलिए एक लंगर आरंभ हुआ जिसका समन्वयन रमदई करती हैं। प्रतिदिन लगभग ८०–८५ लोग इस लंगर में भोजन करते हैं।

से जीवन–यापन कर रही हैं और आशा आश्रम से भी जुड़ी रही हैं.

रमदई बताती हैं कि गावं के लोग कहते हैं कि रमदई के पास न तो घर है न संपत्ति, तब वो कैसे चुनाव लड़ने जा रही हैं?

रमदई ने जीवन में कई परेशानियाँ झेली. प्रक्रिया–तहत निवेदन किये रमदई को २ साल से अधिक अवधि हो गयी है पर उनको अबतक विधवा पेंशन नहीं मिली है. गावं में कम–से–कम १५ ऐसे मामले हैं जहां लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है. उसी तरह, इंदिरा आवास, नाले, खडंजे, आदि जैसे गावं के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी रमदई कारवाई चाहती हैं. रमदई कहती हैं कि वो अगर जीत गयीं तो सब निर्णय वो खुली बैठक में ही लेंगी जिसमें गावं और क्षेत्र के सभी लोग भाग ले सकें. वें कहती हैं कि सब लोग जब समर्थन देंगे तब ही वो कार्य कर पाएंगी.

— सी.एन.एस.
hindi.citizen-news.org

प्रक्रिया–तहत निवेदन किये रमदई को २ साल से अधिक अवधि हो गयी है पर उनको अबतक विधवा पेंशन नहीं मिली है. गावं में कम–से–कम १५ ऐसे मामले हैं जहां लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है. उसी तरह, इंदिरा आवास, नाले, खडंजे, आदि जैसे गावं के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी रमदई कारवाई चाहती हैं. रमदई कहती हैं कि वो अगर जीत गयीं तो सब निर्णय वो खुली बैठक में ही लेंगी जिसमें गावं और क्षेत्र के सभी लोग भाग ले सकें.

लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का राजनीति पर नियंत्रण: अजीत झा

डॉ. अजीत झा, प्रोफेसर, इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं सदस्य, लोक राजनीति मंच अध्यक्षीय मंडल, लखनऊ में 7 जनवरी को हुयी लोक राजनीति मंच की बैठक में भाग ले रहे थे।

अजीत जी ने कहा कि राजनीति में लोक का महत्व हमेशा से नहीं रहा है। राजनीति हथियार से रही है, जो हथियार पर कब्जा कर सकते थे, वो राजनीति पर कब्जा करते रहे। राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई और देश में लोकतंत्र स्थापित करने की लड़ाई दोनों भारत में आजादी से पूर्व एक साथ हुईं। डॉ झा ने कहा कि सारे दुनिया में ये नहीं हुआ, भारत में जनता की आजादी और लोकतंत्र दोनों साथ आये हैं।

अजीत जी ने कहा कि आजादी के पश्चात् कांग्रेस का सत्ता का पक्ष हावी होने लगा और जन आन्दोलन का पक्ष कमजोर होता चला गया। सन १९८० के बाद यदि देखा जाए, तो सभी मुख्य धरा की राजनीति पार्टियाँ या तो प्रदेश में या फिर राष्ट्रीय–स्तर पर सत्ता में रही हैं। इसका अनुभव अच्छा नहीं रहा है, और वो जमात जिनके बल पर वो सत्ता में आई थीं, उनके लिये भी निराशाजनक ही रहा है।

अजीत जी ने कहा कि जो आज राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता पर काबिज हो कर अपने फायदे के लिये जो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आजादी से पहले महात्मा गाँधी एवं डॉ० बी०आर० आंबेडकर के नेतृत्व में जन–आन्दोलन एवं राजनीति एक हो गयी थी। आजादी के पश्चात् राजनीति की असफलता की वजह से ही जन–आन्दोलन बढ़ने लगे हैं। राजनीति और जन–आन्दोलन का भेद अच्छा नहीं है। जन–आन्दोलन की राजनीति करने के बिना ये अपेक्षित बदलाव संभव नहीं है।

अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम राजनीतिक मैदान में कूदे। अजीत जी का कहना है कि यह प्रश्न नकली है। संघर्ष बनाम राजनीति का मसला नहीं है हमारे सामने, कहना है डॉ झा का। आजादी के पहले भी जब महात्मा गाँधी एवं डॉ० बी०र० आंबेडकर का नेतृत्व आया था तब सामाजिक कार्य एवं राजनीतिक कार्य में फर्क नहीं रहा था, और लोगों को एहसास हो गया था कि ऐसा सवाल कि 'राजनीति बनाम संघर्ष' नकली हैं।

अजीत जी का कहना है कि जनता खुद को संगठित कर रही है, जनता की ही राजनीति है, और जनता ही संघर्षरत है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का राजनीति पर नियंत्रण।

संसद और विधान सभाएं जो हैं वो लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी तो गयी हैं पर जनता की भावनाओं और जरूरतों का, प्रतिबिम्ब नहीं करती. तो कई बार बहुत बड़ी ताकतों को भी हताशा होती है. अजीत जी ने कहा कि दूसरी तरफ, समाज में और राजनीति में, संसद और विधान सभाओं के बाहर, कभी भी ऐसी हताशा की स्थिति नहीं रही है, हमेशा लगातार संघर्ष और आन्दोलन चलते रहते हैं. एक और पहलु है कि संघर्ष और आन्दोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव से दूर भागता रहा है. चुनाव में भागीदारी नहीं करना चाहता रहा है, और वो इसको प्रभावहीन समझता रहा है.

अजीत जी ने कहा कि अब यह बदलाव आया है कि संघर्षों और आंदोलनों का एक बहुत हिस्सा यह मानने लगा है कि चुनावी हस्तक्षेप भी जरूरी है चाहे इसमें जितना भी समय लगे और इसमें हमारी हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए.

हमें अनेक मोर्चा, दल, मंच अदि देखने को मिलते हैं जो वैकल्पिक राजनीति की बात रखते हैं. जन–पक्षीय राजनीतिक समूहों में तालमेल और एकता ज्यादा हो और चुनाव में हस्तक्षेप तालमेल के साथ ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा अजीत जी का मानना है.

लखनऊ की ७ जनवरी बैठक का यह मकसद नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो भी जन–पक्षीय राजनीति करे वो लोक राजनीति मंच का हिस्सा हो, बल्कि यह अधिक जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग राजनीति जन–पक्ष में करें. उसका आधार क्या होगा, न्यूनतम शर्ते क्या होंगी, और किन लोगों के साथ लोक राजनीति मंच का तालमेल हो सकता है इस बात पर भी चर्चा हुयी। (**सी.एन.एस.**)

अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम राजनीतिक मैदान में कूदे। अजीत जी का कहना है कि यह प्रश्न नकली है। आजादी के पहले भी जब महात्मा गाँधी एवं डॉ० बी०आर० आंबेडकर का नेतृत्व आया था तब सामाजिक कार्य एवं राजनीतिक कार्य में फर्क नहीं रहा था, **और लोगों को एहसास हो गया था कि ऐसा सवाल कि 'राजनीति बनाम संघर्ष' नकली हैं।**

जन–विरोधी और लोकतंत्र विरोधी 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति के खिलाफ जन–पक्षधर राजनीति जरूरी

जन संघर्ष मोचा के लाल बहादुर सिंह जी, जो 7 जनवरी को लखनऊ में हुयी लोक राजनीति मंच की बैठक में भाग ले रहे थे, ने कहा कि हर तरह के अपराध, भ्रष्टाचार और अपराध को इस मजबूरी के नाम पर उचित समझाया गया है कि जनता बहुमत नहीं बना रही है और इसीलिए तमाम तरह के समझौते करे जा रहे हैं.

लाल बहादुर जी ने कहा कि २००७ में उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडा–राज से त्रस्त हो कर किसी जनवादी विकल्प के अभाव में मायावती जी के नेत्रित्व में बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत दी थी. परन्तु उत्तर प्रदेश की हालत पहले से भी खराब हो गयी और भ्रष्टाचार के नए–नए कीर्तिमान गत–वर्षों में स्थापित हुए. आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दलित महिलाएं मिल जाएँगी जो अपने सर पर मैला ढोने को मजबूर हैं, यह भी इस प्रदेश की सच्चाई है जहां एक दलित महिला मुख्य मंत्री है.

लाल बहादुर जी ने कहा कि मायावती जी ने कार्यभार सँभालते ही उत्तर प्रदेश में नयी कृषि नीति लागू की थी परन्तु इसका घोर विरोध हुआ. यह कृषि नीति मूलतः हमारे प्रदेश के गरीब किसानों की जमीनों को उद्योग–वर्ग को देने की बात रखती थी. नयी कृषि नीति की घोषणा

होते ही मुकेश अम्बानी के 'रिलाइंस फ्रेश' नामक स्टोर जगह–जगह खुलने शुरू हुए ही थे कि व्यापार मंडल ने पुरजोर विरोध करना आरंभ किया. जब बनारस और अन्य जगह पटरी दुकानदारों और व्यापार मंडलों ने पत्थर चलाना और आग लगाना शुरू किया तब संभवतः मायावती जी को लगा कि यह नयी कृषि नीति भारी पड़ेगी और अगले ही दिन उस नयी कृषि नीति को वापस लेने का निर्णय घोषित किया.

लाल बहादुर जी ने कहा कि पिछले दिनों में हमने दिल्ली संसद में देखा कि जब–जब अल्प–संख्यक कांग्रेस सरकार पर खतरा आया तो मायावती और मुलायम दोनों ने ही कांग्रेस को बचाया. चाहे वो भारत–अमरीका परमाणु समझौता रहा हो या महंगाई। अभी हाल ही में सरकारी लोकपल विधेयक पर हुई बहस में मायवती और मुलायम दोनों के दलों ने 'वाक–आउट' कर के कांग्रेस सरकार को हरी झंडी दी – यदि वो बहस करते और लोकतान्त्रिक संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ाते तो कांग्रेस सरकार मनमानी नहीं कर

सकती थी और या तो वो मजबूत लोकपाल लाने के लिये मजबूर होती या फिर उसको वापस लेना पड़ता. मगर मायावती और मुलायम दोनों के ही दलों ने इसको बचाया. परन्तु उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि दोनों दलों के बीच कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो!

लाल बहादुर जी ने कहा कि आंकड़ें बताते हैं कि आजादी के समय उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ और 'बीमारू' राज्य नहीं था. उत्तर प्रदेश तो उस समय के तरक्की–शुदा राज्यों की कतार में था. वहाँ से गिरते–गिरते ४० साल के कांग्रेस–सरकार के राज्य काल में उत्तर प्रदेश 'बीमारू' राज्य की श्रेणी में पहुँच गया.

यह 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति जो आजकल व्याप्त है, वो न केवल जन विरोधी है बल्कि लोकतंत्र विरोधी भी है. लाल बहादुर जी ने कहा कि 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति की जरूरत है लोकतंत्र का खात्मा या लोकतंत्र की हत्या. इसलिए जन–विरोधी और लोकतंत्र विरोधी 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति के खिलाफ जन–राजनीति या जन–पक्षधर राजनीति की जरूरत है.

लाल बहादुर जी ने कहा कि जो जन–पक्षधर पार्टियाँ हैं, उनको एक साथ आ कर के सामाजिक बदलाव, जो हम सभी का दूरगामी लक्ष्य है, के लिए इक्ठ्ठे प्रयासरत रहना चाहिए। उन सब के लिये चुनाव भी एक हथियार है, जितना भी हम को वोट मिलेगा, जितने भी हमारे साथी आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जनता की ताकत आगे बढ़ेगी समाज में. इस तरह का एक प्रयोग पहले भी हुआ है जिसमें जन संघर्ष मोर्चा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, सोशलिस्ट पार्टी, आदि शामिल रहे हैं। लाल बहादुर जी ने कहा कि संदीप पाण्डे जी का जनवादी आन्दोलन के लिये हमेशा से समर्थन रहा है।

आगामी फरवरी 2012 विधान सभा चुनाव में लोक राजनीति मंच 6 उम्मीदवारों को समर्थन दे रहा है जिनका विवरण पृष्ठ संख्या 2 पर दिया गया है। (**सी.एन.एस.**)

यह 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति जो आजकल व्याप्त है, वो न केवल जन विरोधी है बल्कि लोकतंत्र विरोधी भी है. 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति की जरूरत है लोकतंत्र का खात्मा या लोकतंत्र की हत्या. इसलिए जन–विरोधी और लोकतंत्र विरोधी 'कारपोरेट' या उद्योग की राजनीति के खिलाफ जन–राजनीति या जन–पक्षधर राजनीति की जरूरत है.

किसान खत्म नहीं हो रहा, खत्म किया जा रहा है: ब्रह्म देव शर्मा

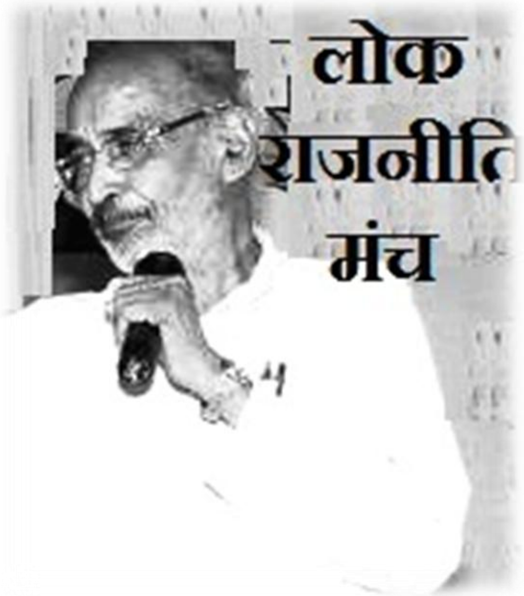

ब्रह्म देव शर्मा, पूर्व कलेक्टर, बस्तर, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आयोग, ने 7 जनवरी को लखनऊ में हुयी लोक राजनीति मंच की बैठक में सक्रिय भाग लिया।

ब्रह्म देव जी ने कहा कि '**जोते बोये काटे धान, खेत का मालिक वही किसान**' जैसी बात अब खत्म हो गयी है. सन २००० की कृषि नीति में यह लिखा हुआ है कि जमीन खाद आदि के लिये पैसा चाहिए, पैसा किसान के पास है नहीं, पैसा सरकार के पास है नहीं, इसीलिए जब पैसे वाला खेती करेगा तो किसान खेत पर काम करेगा.

ब्रह्म देव जी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी से हाथ मिलाओ और यदि हाथ सख्त है तो किसान का है, परन्तु अब यह हालत है कि पुलपुले हाथ वाले किसानी जमीन खरीद रहे हैं, जमीने दे रहे हैं, और जितना जमीन का मूल्य नहीं हैं उतनी कीमत दे कर कृषि भूमि खरीदी जा रही हैं. अभी आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे ही किसानों का कहना है कि खेती में लागत अधिक है और आमदनी कम. ऐसा पहली बार हो रहा है कि खेती नहीं करो तो फायदा है. ब्रह्म देव जी जब वहां गये तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़े जमीनदारों का वर्चस्व है. इन जमीनदारों ने यह भी कहा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कारण हमें मजदूर नहीं मिल रहा है और इसीलिए हमें कृषि में मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए. इन मशीनों पर ६० प्रतिशत तक की छूट ('सब्सिडी' या अनुदान) मिल रही है. कुल मिला कर प्रश्न यह है कि किसान खत्म हो रहा है या खत्म किया जा रहा है?

ब्रह्म देव जी ने यह सवाल सभी राजनीतिक दलों को लिखे पर किसी ने भी इस पर कोई करवाई नहीं की. यह तो कोई कही नहीं रहा है कि किसान खत्म किया जा रहा है, हर ओर सिर्फ यही

सुनने में आता है कि किसान खत्म हो रहा है.

क्या खेती अकुशल काम है?

ब्रह्म देव जी ने पूछा कि अब आप ही यह बताइए कि कृषि कुशल काम है कि अकुशल? जब कृषि कुशल काम है और बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, तब यह सरकार द्वारा अकुशल क्यों माना जाता है? खेती–किसानी को सरकार ने अकुशल काम का दर्जा दिया. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में यह साफ कहा गया है कि खेती अकुशल काम है.

ब्रह्म देव जी ने कहा कि किसानी को अकुशल काम का दर्जा दे कर किसानी के मूल्य को आधा कर दिया गया क्योंकि सरकारी दरों के अनुसार कुशल और अकुशल काम में आधे का अंतर है.

आजादी के बाद जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना तो उसमे यह स्पष्ट कहा गया है कि किसान को उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिसमें उसका और उसके परिवार का भरण–पोषण हो सके. **अब परिवार की परिभाषा क्या है?** परिवार में, छठें वेतन आयोग के अनुसार औसतन पांच लोग हैं: महिला, पुरुष, २ बच्चे और एक बुजुर्ग. बच्चों को दैनिक जरूरतों के मापदंड से आधा सदस्य माना गया है जबकि व्यवहारिकता यह है कि बच्चों पर निवेश संभवतः अधिकतम होता हो. कुल मिला कर सरकार ने (और लोगों ने भी) यह मान लिया कि परिवार में ३ सदस्यों के बराबर भरणपोषण की आवश्यकता होती है और इतनी मजदूरी किसान को मिलनी चाहिए. असलियत भले ही यह हो कि परिवार में ५ लोग हों. सीधा तात्पर्य है कि ५ लोगों के परिवार को ३ लोगों के भरणपोषण का इंतजाम होगा तो प्रश्न उठेगा कि किसान खत्म हो रहा है या कि खत्म किया जा रहा है?

ब्रह्म देव जी ने कहा कि हम सब को यह सोचना चाहिए कि किसान को कहाँ से घाटा हो रहा है. जो किसान की कड़ी मेहनत का न्यूनतम वाजिब मूल्य है उसका आधा ही तो हम उसको दे रहे हैं. फिर हम कहते हैं कि किसान खत्म हो रहे हैं, जब कि असलियत यह है कि किसान खत्म किये जा रहे हैं.

दस्तावेज कहते हैं कि परिवार में दो लोग

> ब्रह्म देव जी ने कहा कि किसानी को **अकुशल काम** का दर्जा दे कर किसानी के मूल्य को आधा कर दिया गया क्योंकि सरकारी दरों के अनुसार कुशल और अकुशल काम में आधे का अंतर है.
>
> जितना किसान की कड़ी मेहनत का न्यूनतम वाजिब मूल्य है उसका आधा ही तो हम उसको दे रहे हैं. फिर हम कहते हैं कि किसान खत्म हो रहे हैं, जब कि असलियत यह है कि किसान खत्म किये जा रहे हैं.

कमा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? पुरुष के अलावा या तो महिला को मजबूरन काम करना पड़ रहा है, या फिर बच्चे को शिक्षा छोड़ काम करना पड़ रहा है, या फिर परिवार में बुजुर्ग को भी मजबूरीवश काम करना पड़ रहा है.

सरकार के छठें वेतन आयोग के अनुसार परिवार को पांच लोगों की यूनिट माना जाता है. परन्तु किसान या असंगठित मजदूर वर्ग, जो भारत की जनता का ६० प्रतिशत भाग है, उसके परिवार में सिर्फ २ लोगों को रोजगार देने की बात होती है.

स्वभाविक है कि यदि किसान को इतनी मजदूरी मिल जाए जो उसके पूरे परिवार के लिये सही मायने में पर्याप्त है, तो फिर महिला क्यों मजदूरी करेगी, बच्चे शिक्षा त्याग कर क्यों मजदूरी करने पर विवश होंगे? शहरों में तो कुछ लोगों को एक–एक लाख रुपया वेतन मिल रहा है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों का वैद्यानिक तरीके से शोषण हो रहा है! अनुमान लगाया गया है कि एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्रति–गाँव शोषण हो रहा है.

किसान और बैंक का कर्जा/ ब्याज

ब्रह्म देव जी ने कहा कि हमारे कानून में शुरू से ही यह साफ लिखा हुआ है कि खेती–किसानी में बैंक से कर्जा लेने पर ४ प्रतिशत से ज्यादा सामान्य ब्याज नहीं होगा. लेकिन जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और सरकार ने हाथ खींच लिये तो स्थिति बदल गयी. यह हाल जब बैंकों का है तो साहूकार की मनमानी का तो कहना ही नहीं है!

आज हालत यह है कि कृषि–सम्बंधित कर्जे पर काफी अधिक चक्रवर्ती ब्याज धड़ल्ले से लग रहा है जो कि कानूनन माना है. जिन शर्तों पर ब्याज दिया जा रहा है उन शर्तों पर हस्ताक्षर करते वक्त अगर आप पढ़ें तो पायेंगे कि उनमें साफ लिखा हुआ है कि आप अदालत नहीं जा सकते. ब्रह्म देव जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक में इस बात की रपट की परन्तु कोई करवाई नहीं हुई.

शुरुआत में जब बैंक सम्बंधित कानून बना तो उसमें यह साफ कहा गया था कि अदाएगी ३५ साल से अधिक में नहीं होनी चाहिए. आज हालत यह है कि अदाएगी १–५ साल में ही सीमित हो गयी है जिसके कारण मासिक किश्त काफी अधिक हो गयी है. पहले जब अदाएगी ३५ साल में होती थी तब रुपया १ लाख के कर्ज में मात्र रुपया ५ हजार वार्षिक किश्त बनती – परन्तु आज कल जब अदाएगी १–५ साल में होनी है तो निःसंदेह किश्त कई गुणा अधिक है.

ब्रह्म देव जी ने कहा कि यदि अदाएगी नहीं हो पाती है तो यह केस कोर्ट में जाएगा और 'सिविल' जेल तक हो सकती है. 'सिविल' जेल का मतलब यह है कि जेल में रहने का खर्चा आदि सब देना पड़ता है.

ब्रह्म देव जी ने कहा कि साफ जाहिर है कि किसान खत्म नहीं हो रहा है बल्कि खत्म किया जा रहा है और इस पर अंकुश लगाने की और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है.

– सी.एन.एस.

hindi.citizen-news.org

महिला असमानता और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध:

अनीता श्रीवास्तव, वराणसी उत्तरी से प्रत्याशी

अनीता श्रीवास्तव, लोक राजनीति मंच की ओर से आगामी विधान सभा चुनाव में वाराणसी (उत्तरी) क्षेत्र से प्रत्याशी हैं।

१६६८ में जब सर्व शिक्षा अभियान आया था तब अनीता सबसे कम आयु की व्यक्ति थीं जो 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर रही थीं. जब अनीता हाई–स्कूल में थीं तब से ही उन्होंने अपने आस–पास की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और फिर औपचारिक स्कूल में भर्ती होने के लिये प्रेरित किया. काशी विद्यापीठ में आने पर अनीता राजनीतिक शास्त्र की भी विद्यार्थी रहीं और वो अखिल भारतीय छात्र संगठन ('आइसा') से जुड़ी रहीं. अनीता की रुचि खेल में विशेष रही और वो राष्ट्रीय स्तर की 'जुडो' की चौम्पियन रही हैं. काशी विद्यापीठ में उन्होंने देखा कि लड़कियां अक्सर शिक्षकों तक से झिझकती थीं. हालॅाकि उनके साथ तो पारिवारिक और सामाजिक दोनों का समर्थन रहा परन्तु अनेक लड़कियों को जिन्हें पारिवारिक या सामाजिक सहयोग नहीं मिलता, उनके अन्दर जो प्रतिभाएं हैं वो दबी रह जाती हैं. अनीता को भी जब कोरिया देश में अपनी खेल प्रतिभा दिखने का अवसर मिला तब उनके संयुक्त परिवार ने जाने नहीं दिया. अनीता ने तब **जुझारू विद्यार्थी संगठन** बनाया.

अनीता ने शिक्षा के बाद ग्रामीण क्षेत्र में महिला मुद्दों पर काम करते वक्त **जुझारू महिला संगठन** बनाया और २००६ में, सब को मिला कर '**प्रगतिशील जन संगठन**' की नींव पड़ी. हाल ही में अनीता ने युवा केंद्र के राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम में ३ साल

तक भाग लिया और २०१० में उन्हें आयुक्त द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ युवा कार्यकर्ता' पुरुस्कार, प्रशस्ति पत्र और रुपया १०,००० का इनाम मिला.

अनीता का कहना है कि २०१० में हम सभी को लग रहा था कि चुनाव में अच्छे लोगों को भी आगे आना चाहिए. इसीलिए सबकी सर्वसम्मिति से २०१० में हमने पंचायत चुनाव में ४ महिला और १ पुरुष प्रत्याशी खड़े किये, जिनमें से जिला बी. डी.सी., जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव शामिल थे. इनमें से हमारे संगठन से एक महिला और एक पुरुष प्रधान बने, और जिला बी.डी.सी. चुनाव में हमारी प्रत्याशी ४५ वोट से दूसरे नंबर पर रही और जिला पंचायत चुनाव में हमारी प्रत्याशी ५५ वोट से दूसरे नंबर पर रही. जब विधान सभा चुनाव आया तो हमने अपने साथियों के साथ कई दौर बैठकें कीं और निर्णय लिया कि हमें अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और सभी प्रगतिशील जनवादी संगठनों को एकजुट करके एक साझा प्रयास और साझी सोच के साथ हम सब को विधान सभा चुनाव में आना चाहिए.

अनीता का कहना है कि वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध करने का आगामी चुनाव एक सशक्त तरीका है और हमसब को लगा कि इसी तरह से हम राजनीति में भी हस्तक्षेप करें और अपने विचारों और सिद्धान्तों को जनता के बीच में ले जाएँ.

अनीता के अनुसार उनकी महिला मुद्दों के प्रति विशेष प्रतिबद्धता है. अनीता का कहना है कि हमसब ने देखा कि कैसे महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दल कतरा रहे हैं. हमारा सवाल है कि ४ मुख्यधारा की पार्टियों को, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और समाजवादी पार्टी, को पार्टी के भीतर ५० प्रतिशत महिला आरक्षण देने से कौन रोक रहा है? न सही ५० प्रतिशत पर महिला प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए कुछ तो नीति तय करें. यदि दलित पार्टी है तो दलित महिलाओं को ही आरक्षण दें, अल्प–संख्यक पार्टी है तो अल्प–संख्यक महिलाओं को आरक्षण दे, पिछड़े लोगों की पार्टी है तो पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दे, अगर सवर्ण पार्टी है तो सवर्ण महिलाओं को आरक्षण दे, पर यह कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है.

महिलाओं की भागीदारी को आखिर कैसे बढ़ाया जाए यह संगीन सवाल है. अनीता का कहना है कि उनकायह भी मानना है कि पंचायत में भी महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी होनी चाहिए. उनका यह भी मानना है कि हर शैक्षिक संस्थान में यौन उत्पीड़न समिति होनी चाहिए जिसका प्रभावकारी क्रियान्वन भी हो. महिला हिंसा कानून को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से बाहर निकाल कर कानून मंत्रालय में लाना चाहिए और महिलाओं की भागीदारी से ही इस कानून को सशक्त रूप से लागू करना चाहिए.

हमें अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और सभी प्रगतिशील जनवादी संगठनों को एकजुट करके एक साझा प्रयास और साझी सोच के साथ हम सब को विधान सभा चुनाव में आना चाहिए

कैफी आज़मी की याद में

'आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है,
आज की रात न फुटपाथ ये नींद आएगी
सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठों, तुम भी उठों,
कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी'

इस शेर की पैदाईश आजमगढ़ जिले के गाँव—मिजवाँ में हुई थी। मिजवॉ के एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में 19 जनवरी 1921 को सैय्यद फतह हुसैन जिवी और कनिज फात्मा के चौथे बेटे के रूप में अतहर—हुसैन रिज्वी का जन्म हुआ जो बाद में कैफी आजमी नाम से एक मशहुर शायर, रंगकर्मी, समाजसेवी, फिल्मकार (गीत, कहानी, पटकथा, संवाद, अभिभाव) के रूपों में प्रतिष्ठित हुआ।

इसके अतिरिक्त छात्र युनियनों, मजदूर सभा 129 ट्रेड युनियनों में काम करते हुए जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे वे कुट वामपंथी थे।

अपने देश के गांवो की उर्वरक क्षमता पर गर्व होता है और कभी—कभी इश्क भी कि क्यों अपना जन्म शहर में हुआ ? क्यों नहीं हमने प्रेमचन्द के लमहीं, धुमिल के खेवली या कैफी के निजवा में जन्म लिया ?

खैर कैफी की शिक्षा मदरसों में हुई और उनको संस्कार पूरे दीनी (इस्लामिक) मिले और भविष्य में उनका वामपंथी नेता बनना उस पूरे सिद्धान्त को गलत ठहरा देता है जिसमें व्यक्तित्व का निर्धारक एवं निर्माणक सिर्फ वंशानुक्रम एवं वातावरण ही होता है।

कैफी का पहला कविता संग्रह झनकार — 1943, अखिरेशब—1992 में उनके पूर्व प्रकाशित संग्रहो की चुनी हुई कविताएं सरमाप नाम से प्रकाशित हुई। कैफी साहब ने फिल्मों में काफी गीत लिखे, 1974 में प्रकाशित मेरी आपण जूनों में उनके 40 फिल्मी नामें संग्रहीत है।

कैफी बम्बई से निकलने वाले अजबार 'पब्लिट्ज' में कई वर्षो तक व्यंग्य कॉलम लिखते रहे है, इस पूरे व्लगम संग्रह को 2001 में 'नई गुलिस्ता नाम से (दो खण्डों के) प्रकाश की किया गया।

1943 में बम्बई में 'इप्टा' का गठन हुआ, कैफी को बम्बई शाखा का

अध्यक्ष चुना गया, इसके बाद वो लम्बे समय तक इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे।

भारत–पाक बँटवारे पर बनी उनकी फिल्म 'गरम हवा' को आप भी विशेष दर्जा प्राप्त है। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवाद कैफी साहब ने ही लिखे थे। फिल्म के लिए उन्हें तीन–तीन फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पद्मश्री के साथ ही आपको आबकारा सज्दे संग्रह पर उ0प्र0 उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी पुरष्कार सोवियत इनि नेहरु पुरस्कार, अफ्रो एशियाई लेखक संघ पुरष्कार, गालिब पुरष्कार, हिन्दी अकादमी दिल्ली का शताब्दी सम्मान, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी सम्मान, विश्व भारती विदि ने कैफी को डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित किया।

कैफी के गुरबत के दिनों के एक कमो की रिहाईश हो यह आलिशान, 25 जानकी कुटीर जूहू, मुम्बई, दोनो जगहो पर ही रहने वालों में उनके दोस्तों को अभी गुरेज नही रहा, ख्वाजा अहमद अब्बास, भीष्म साहनी, बेगम अख्तर, मजरुह सुल्लतानपुरी, जोश मलीहाबादी, फौज अहमद फौज, किराम गोरखपुरी जैसी हस्तियां मुम्बई में होती थी तो कैफी के घर होती थी। 1973 में फालिज के शिकार होने के बाद कैफी ने निजदो की ओर बायसी कर ली, लकवाग्रस्त कैफी अपनी 'ब्हील चेयर' के साथ अपने साधनहीन गांव मिजवा की हर लड़ाई में आगे दिखने लगे अपनी धरती, अपने लोग का भावात्मक लगाव और मिजवा के विकास का सपना कैफी के मन में बैठ गया।

साहित्य आयोजन हो, इप्टा की प्रस्तुति, मजदूर किसान, छात्रों की कोई भी सभा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या साम्प्रदायिकता का विरोध हो कैफी हर जगह दिखाई देते थे।

फुलपुर रेलवे स्टेशन बन्द किये जाने के विरोध में रेल रोकों आन्दोलन में वे 'ब्हील चेयर' के साथ ही पटरीयों के बीच आकर बैठ गये थे।

अपने गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क, स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, टेलीफोन जो कुछ भी मिजवा में आज है वो कैफी के संकल्प एवं संघर्ष का ही नतीजा है। इतना ही नहीं मृत्यु के ठीक तीन वर्ष पूर्व कैफी मिजवा की एक जनसभा में अपनी बेटी शबाना आज़मी से एक संकल्प भी दिलवा लेते है कि उनके न होने के स्थिति में उनके सपनों को पुरा करने की जिम्मेदारी शबाना की होगी।

प्रगतिशील विचारधारा का यह रौशन नजर व्यक्तित्व 10 मई 2002 को हम सबकों यह कहते हुए चल दिया किः

खार व खस तो हटे, रास्ता तो चले।
मैं अगर थक गया, काफीला तो चले।।
बेल्चे लाओं खोदो जमीन की तहे।
मैं कहाँ दफन हूँ पता तो चले।।

– धनंजय त्रिपाठी

सरकारी कर्मचारी को जब पूरा वेतन समय से मिलता है तो क्यों घूस माँगते हैं?

सुषमा, सफीपुर (सुरक्षित), उन्नाव से प्रत्याशी

सुषमा, जो आशा परिवार के साथ जन मुद्दों पर कार्यरत हैं, वो इस २०१२ विधान सभा चुनाव में लोक राजनीति मंच की ओर से सफीपुर (सुरक्षित), उन्नाव से प्रत्याशी हैं.

सुषमा ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आंगनवाड़ी की कार्यकुशलता, स्कूल में 'मिड-डे मील' या अपराह्न भोजन की गुणात्मकता आदि से जुड़े मुद्दों पर गत वर्षों में कार्य किया है.

कई लोग बिना काम किये मजदूरी ले लेते हैं, या फिर सरकारी कर्मचारी जो काम करने के लिये उनको वेतन मिलता है, उसके लिये घूस मांगते हैं, ऐसे मुद्दों पर सुषमा सक्रियता से अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं. सुषमा कहती हैं कि उनको यह समझ नहीं आता कि सरकारी कर्मचारी जैसे कि बी.डी.ओ., स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस आदि क्यों पैसा मांगते हैं जब उनको पूरा वेतन समय से मिलता है. सुषमा का कहना है कि सरकारी कर्मचारी 'जनता का गुलाम हैं' और उनको सेवा भाव और इमानदारी से काम करना चाहिए.

सुषमा का कहना है कि यदि वो जीत गयीं तो निर्णय खुली बैठक में लेंगी जिससे जनता की सहभागिता बढ़ सके. यदि वो जीत गयीं तो सुषमा कहती हैं कि जिन मुद्दों पर वो कार्य करेंगी वो भी उन्हें जनता ही बताएगी. – **सी.एन.एस.**

सुषमा का कहना है कि यदि वो जीत गयीं तो निर्णय खुली बैठक में लेंगी जिससे जनता की सहभागिता बढ़ सके.

पैगाम–ए–अमन कारवाँ : अयोध्या से अमृतसर

अयोध्या और पंजाब दोनों ही अपनी विशिष्ट रूहानी विरासत के कारण भारत में अपना विशिष्ट पहचान रखता है। अयोध्या का अर्थ "वह भूमि जहाँ कभी युद्ध नहीं होता हो भी है। यह आर्यो, बौद्ध भिक्खुओं, जैन मुनियों, सूफी सन्तों एवं सिक्ख गुरूओं के आकर्षण का केन्द्र रहा है। मध्यकाल में सूफी लोग पाँच नदियों वाली पंजाब के मैदानी भागों में शान्ति और भाईचारे के सन्देश के साथ यहाँ आये और यहाँ पर अध्यात्मिक केन्द्र स्थापित किया। गुरूनानक देव का यह छन्द "अव्वल अल्ला नूर उपाया, कुदरत के सब वन्दे" काफी प्रचलित है, उन्होंने जन–जन तक मानवता का सन्देश पहुँचाया।

1 दिसम्बर 2011 को भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव एवं द इण्डिया हारमोनी फाउण्डेशन के संस्थापक जफर सैफुल्लाह साहब के पहल पर अयोध्या से अमृतसर तक पैगाम–ए–अमन कारवाँ निकाली गयी। इसका मकसद था, पंजाब और अयोध्या के साझा संस्कृतियों के इन दो पवित्र स्थलियों को एकदूजे के इतना करीब ला देना कि नफरत फैलाने वाले धर्म और मजहब की आड़ में खुँरेजी के खेल खेलने की सोच भी न सकें। इस यात्रा का नेतृत्व चिश्ती सद्भावना पुरस्कार प्राप्त युगलकिशोर शरण शास्त्री ने किया था। आशा परिवार और अयोध्या की आवाज इस कारवाँ के आयोजन में सहयोगी की भूमिका अदा की थी। कारवाँ में कुल 36 लोग शामिल थे जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध

भिक्खु के अलावा महिलाओं की भी संख्या डेढ़ दर्जन के आस–पास थी।

पैगाम–ए–अमन कारवाँ के पूर्व संध्या पर सरयूकुंज सर्वधर्म सद्भाव केन्द्र अयोध्या में अवध पीपुल्स फोरम द्वारा लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साम्प्रदायिकता, मर्दानगी, बार्डर के पार एवं सैन्यकरण लघु फिल्मों के प्रदर्शन के पश्चात परिचर्चा करायी गयी। इस अवसर पर केरल प्रान्त में स्थित जनपद त्रिचूर के सालसा सलवीन ग्रीन स्कूल के बच्चों ने 'इश्क न हिन्दू इश्क न मुस्लिम' गीत से पूरी शाम को अमन के रंग में रंग दिया।

1 दिसम्बर 2011 को प्रातः 9 बजे हनुमानगढ़ी के सुप्रसिद्ध सन्त एवं समाजवादी सन्त सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा भवनाथ दास जी महाराज ने हरी झण्डी दिखाकर सरयूकुंज अयोध्या से रवाना किया। कारवाँ के जत्थों ने विभिन्न विद्यालयों के समारोहों एवं गोष्ठियों एवं पत्रकों के माध्यम से अमन और भाईचारे का सन्देश देते हुए लखनऊ पहुँचकर

गाँधी भवन में पहला पड़ाव डाला जहाँ पर आशा परिवार की ओर से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त संदीप पाण्डेय, शहला घानिम एवं बाबी रमाकान्त ने पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया। यह कारवाँ अपने निर्धारित कार्यक्रमानुसार अमन का सन्देश देते हुए 2 दिसम्बर को बरेली, 3 दिसम्बर को मुजफ्फरनगर, 4 दिसम्बर को दिल्ली, 5 दिसम्बर को कुरूक्षेत्र, 7 दिसम्बर को अमृतसर, 8 दिसम्बर को चण्डीगढ़ में पड़ाव डाला। इन सभी स्थलों पर अमन के लिये स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के निर्देशन में अमन और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी रखे गये थे। इसमें गाँधीवादी राम मोहन राय एवं महावीर भाई के संयोजन में विभिन्न कस्बों व शहरों मे पीस मार्च एवं जलसे का आयोजन किया गया। कारवाँ में स्थित केरल के बच्चों ने अपने एकता के गीतों से लोगों में बेहतरीन समाँ बाँधा।

पैगाम–ए–अमन कारवाँ का औपचारिक समापन अमृतसर में किया गया था। यहाँ पर कारवाँ के जत्थों ने स्वर्ण मन्दिर में मत्था टेककर प्यार–मोहब्बत, भाईचारा का सन्देश ग्रहण किया। समापन अवसर पर अमृतसर के भवंज एम.एस. स्कूल में अध्यक्ष अविनाश महेन्द्र, उपाध्यक्ष अनिल सिंघल व प्रिन्सिपल डा. अनीता भल्ला के निर्देशन में विशाल समारोह का आयोजन किया गया। साथियों सलाम है, भाइयों सलाम है, बहनों सलाम है, अमन के मौका का यह सलाम था। यह देश भक्ति एवं अमन का गीत पेश किया था ग्रीन स्कूल केरला के बच्चों ने। इस समारोह में हजारों की संख्या में छात्र–छात्रायें एवं नागरिकगण उपस्थित थे। इसके मुख्य अतिथि पूर्व गर्वनर केरला एण्ड बिहार के आर.एल. भाटिया को कारवाँ के संयोजक युगलकिशोर शरण शास्त्री ने अमन का झण्डा भेंट किया। अपने सम्बोधन में श्री भाटिया ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते धर्म के नाम पर विभाजन करने का चाल चल रहे हैं। पैगाम–ए–अमन कारवाँ के मुख्य आयोजक एवं द इण्डिया हारमोनी फाउण्डेशन के संस्थापक जफर सैफ्फुल्लाह ने कहा कि धर्म लोगों को जोड़ने का सन्देश देता है। देश के नामी गिरामी सामाजिक कार्यकर्ता असगर अली इन्जीनियर ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहना

चाहिए। इस अवसर पर अमृतसर मैनेजमेन्ट एसोशिएशन के प्रधान अशोक सेठी, पार्षद बख्शी राम अरोड़ा व अन्य शख्शियतों ने समारोह को सम्बोधित किया।

पैगाम–ए–अमन कारवाँ के समापन में उपरोक्त विद्यालय में सुफियाना का रूहानी सफर पर कार्यक्रम रखा गया। जिसे विख्यात गजल गायक सुश्री रेणे सिंह ने अर्जिया सारी चेहरे पर लिखकर लाया हूँ, तुम से क्या माँगू तुम खुद ही समझ लो मौला, को सुफियाना अंदाज में गाया। उनके साथ नर्तकी शोभा नारायणा ने भी अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। पैगाम–ए–अमन कारवाँ के वापसी के समय चण्डीगढ़ के एक विद्यालय में समारोह रखा गया था जिससे हजारों लोगों ने अमन की प्रेरणा ली।

पैगाम–ए–अमन कारवाँ अपने लक्ष्यों में कितनी सफल रही यह अप्रत्यक्ष है लेकिन यह देश की साझी विरासत के सन्देश को करोड़ों लोगों तक पहुँचाने में सफल रहा है।

– युगलकिशोर शरण शास्त्री

आगामी कार्यक्रमों की सूचनाः

लोकशक्ति अभियान की बैठकें बजट सत्र से पहले निम्नलिखित स्थानों पर होंगी, अधिक जानकारी के लिये दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें:

– ६–११ जनवरी २०१२: आंध्र प्रदेश
– १२ जनवरी २०१२: जन संसद, मुलताई, मध्य प्रदेश
(सुनीलम, ९४२५१०९७७०)
– १३ जनवरी २०१२: इंदौर, मध्य प्रदेश
– २३–२६ जनवरी २०१२: बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़
(कम्यानी ९७७१९५०२४८, गौतम बंदोपाध्याय ९८२६१७१३०४)
– ६–१५ फरवरी २०१२: महाराष्ट्र, गोआ, मध्य प्रदेश (सुनीति ९४२३५७१७८४)

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:
मधुरेश, ९८१८९०५३१६

बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन
२०–२२ जनवरी २०१२
स्थानः ए.आई.सी.यू.एफ. आश्रम, कैम्पियन स्कूल और शाहपुरा झील के निकट, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:
भोपाल: रोली शिवहरे ९४२५४६६४६१, सचिन जैन ९९७७७०४८४७
दिल्ली: दीपा सिन्हा ९६५०४३४७७७, सजल दंद ८१३०२०००६२, वंदना प्रसाद ९८९१५५२४२५

लोक राजनीति मंच की चुनाव हेतु आचार संहिता

१. उम्मीदवार की सामाजिक कामों की पृष्ठभूमि होना अनिवार्य होनी चाहिए. चुनाव जीतने या हारने के बाद भी उसे पहले की तरह आम जनता के मुद्दों पर काम करते रहना चाहिए. यानि चुनाव अपने काम के आधार पर ही लड़ा जायेगा.

२. उम्मीदवार कम–से–कम पैसे में चुनाव लड़ेगा, वह कोई दिखावा नहीं करेगा और अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च नहीं करेगा. खर्च जनता से चंदा ले कर पूरा किया जायेगा. हिसाब–किताब में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी.

३. यदि उम्मीदवार जीत जाता है तो उसकी जीवनशैली में पहले की अपेक्षा कोई खास परिवर्तन नहीं आना चाहिए. पहले की ही तरह वह जनता के लिये सुलभ उपलब्ध होना चाहिए.

४. प्रचार ज्यादा–से–ज्यादा जन–संपर्क द्वारा किया जायेगा न कि और खर्चीले तरीके अपना कर.

५. संगठन के कार्यकर्ताओं के पास जो वाहन हैं उन्हीं का इस्तेमाल प्रचार में किया जायेगा.

६. कोई प्रलोभन दे कर किसी का मत नहीं प्राप्त किया जायेगा न ही किसी को किसी किस्म की धमकी दी जाएगी.

७. उम्मेदवार अपनी सुरक्षा के लिये कोई हथियार नहीं रखेगा और न ही जीतने के बाद हथियारों से सुरक्षा की व्यवस्था करेगा.

८. वह अपने प्रचार के लिये कोई पेशेवर लोगों या तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेगा. उदहारण के लिये पैसा दे कर अखबारों में खबर छपवाना.

९. चुनाव में जो लोग उसका प्रचार करेंगे उन्हें सहयोग की भावना से ऐसा करना चाहिए न कि पैसा ले कर.

१०. चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जायेगा न कि जाति, धर्म, या अन्य इस किस्म के किसी आधार पर.

लोक राजनीति मंच वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने हेतु प्रतिबद्ध

निम्न मुद्दों पर लोक राजनीति मंच की भूमिका हमारी सोच को रेखांकित करती है:

• राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण ताकि विकास नियोजन संबंधी निर्णय ग्राम सभा या स्थानीय निकाय के स्तर पर लिए जा सकें।

• निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण वाली आर्थिक नीतियों के वर्तमान स्वरूप का विरोध तथा प्राकृतिक संसाधनों पर कम्पनियों के कब्जे का विरोध

• हरेक धर्म के लिए सद्भाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना

• खाद्य सुरक्षा हेतु सभी धार्मिक स्थलों पर गुरूद्वारों के समान लंगर की व्यवस्था

• मानव निर्मित विभाजन की श्रेणियों के आधार पर मनुष्य–मनुष्य में भेद करने का विरोध

• वैश्विक व क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण खासकर व्यापक जनसंहार की क्षमता वाले हथियारों की, रक्षा बजट में कटौती, शांति व मैत्री को बढ़वा, सीमा पार लोगों को आने–जाने की छूट

• जाति प्रथा का उन्मूलन किन्तु जातियों में बराबरी स्थापित होने तक आरक्षण की नीति का समर्थन

• हरेक जन प्रतिनिधि या महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर एक महिला व एक पुरूष की व्यवस्था, किन्नरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व

• सैन्य बल विशेषाधिकार अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, जैसे काले कानूनों की समाप्ति

• आतंकवाद व नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष लोगों का उत्पीड़न बंद

• उद्योग व सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि को महत्व दिया जाना, किसानों–मजदूरों को सम्मानजनक आय

• वर्ग विषमता को राजनीतिक निर्णय से खत्म करना

• सिर्फ अमीरों पर कर, इसके लिए एक अमीरी रेखा तय करना

• सार्वजनिक जीवन व प्रशासन के काम में पारदर्शिता व जवाबदेही

• शिक्षा के अधिकार में समान शिक्षा प्रणाली व पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा को शामिल किया जाना

• सभी को मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था

• खाद्यान्न, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण पर रोक

• नाभिकीय उर्जा कार्यक्रम पर रोक, पर्यावरणीय दृष्टि से साफ–सुथरे अक्षय उर्जा स्रोतों को बढ़ावा

• स्वतंत्र फिलीस्तीन राज्य के मुद्दे का समर्थन